

# बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

05 मार्च 2020

----

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह ].

20

----

## कटाव से बचने की कार्रवाई

\*29 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के धपरसिया पंचायत अन्तर्गत मुकुरिया, मोहना चौकी एवं बलिहारपुर ग्रामों एवं इनके इर्द-गिर्द की खेती योग्य भूमि पर महानन्दा नदी द्वारा भीषण कटाव हो रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि महानन्दा नदी द्वारा भीषण कटाव के कारण ऊपर वर्णित ग्रामों एवं इनके इर्द-गिर्द खेती योग्य भूमि के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार प्रभावित गांवों एवं कृषि योग्य भूमि को कटाव से बचाने हेतु त्वरित उपाय करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

## पेंशन की राशि कबतक

\*40 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

**समाज कल्याण :-**

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन और विकलांग पेंशन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 में 3000 (तीन हजार) व्यक्तियों के नाम चयनित कर स्वीकृति हेतु विभाग को वर्ष 2019 के आरम्भ में ही प्रखंड द्वारा भेज दिया गया, लेकिन अभी तक लाभार्थी के बैंक खाते में राशि नहीं पहुँची है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

----

**अनुग्रह अनुदान**

**\*43 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक) :**

**वित्त विभाग :-**

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को सेवाकाल में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि अनुग्रह अनुदान देने के लिए बजट में एक अलग शीर्ष बनाया गया है जिसके कारण नियोजित शिक्षकों को प्रावधान होते हुए भी समय पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान नहीं हो पाता है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सेवाकाल में मृत नियोजित शिक्षकों के परिजनों को उनके वेतन शीर्ष से ही 4 (चार लाख) रुपये का अनुग्रह अनुदान भुगतान करने का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

----

**बाढ़ से स्थायी समाधान**

**\*125 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक) :**

**जल संसाधन :-**

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सूबे में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण जन-धन बुरी तरह प्रभावित होता है तथा खेती-किसानी पर भी ग्रहण लग जाता है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बाढ़ के जल को उसके मूल नदियों से दूसरे नदियों में जोड़ने की योजना साकार करना चाहती है ताकि बाढ़ से उत्पन्न विभीषिका का स्थायी समाधान संभव हो सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

-----

### चोरों का आतंक

\*126 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखण्ड में इन दिनों ट्रैक्टर एवं मोटर साइकिल की चोरी करने वाला गिरोह काफी सक्रिय हो गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 के नवम्बर एवं दिसम्बर तथा वर्ष 2020 के जनवरी माह में परिहार प्रखण्ड के सिसौटिया, कोरियापिपरा, बराही, बेला, मच्छपकौनी तथा परिहार बाजार से दो दर्जन ट्रैक्टर एवं 10 (दस) मोटर साइकिल की चोरी हो गई है, लेकिन अभी तक चोरी करनेवाला गिरोह का पता नहीं चला है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पुलिस बल की सक्रिय गश्ती के बावजूद ट्रैक्टर एवं मोटर साइकिल चोरी का क्या औचित्य है ?

-----

### बसों की सेवा नहीं

\*127 श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार) :

परिवहन :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज से जाने के लिए किसी भी रूट के लिए सरकारी बसों की सेवा नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज नगर की सरकारी बस स्टैंड पर पथ परिवहन विभाग की बसें नहीं बल्कि निजी बसों की कतार लगी रहती है ;

(ग) क्या यह सही है कि गोपालगंज सरकारी बस स्टैंड में सरकारी बसें चलाने की सभी संसाधन उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज में पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ?

----

### बसों का लोकेशन

\*128 प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):

परिवहन :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना में सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण में जगह-जगह बने बस स्टॉप ध्वस्त हो चुके हैं ;

(ख) क्या यह सही है कि सड़कों पर बस स्टॉप नहीं रहने से बसें और गाड़ियां जहां-तहां रोककर सवारी उठाते हैं, जिससे इन दिनों हर रोज इनकम टैक्स, हड़ताली मोड़, शेखपुरा मोड़, सगुना मोड़ आदि जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है और यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनकम टैक्स से सगुना मोड़ एवं अन्य सड़कों पर जगह-जगह स्थलों को चिन्हित कर बस स्टॉप बनवाने तथा बसों का लोकेशन जानने के लिए स्क्रीन लगवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### बैंकों की भूमिका

\*129 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने, ग्राम पंचायत को बैंक शाखाओं व खासकर गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति लाख आबादी पर 12.52 की जगह बिहार में मात्र 7.7 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4.01 बैंक की शाखाएं हैं । एटीएम की उपलब्धता भी प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत 18.31 की तुलना में बिहार में मात्र 7.43 तथा ग्रामीण क्षेत्र में महज 1.42 है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार और किसानों की सहायता के लिए बैंकों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए क्या करेगी ?

-----

### सिंचाई उपलब्ध कबतक

\*130 श्री राम लषण राम रमण (मनोनीत):

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखण्ड की भटसीमर पश्चिमी पंचायत में पश्चिमी कोशी नहर से मलहनमा, भटसीमर और मैलाम की तरफ जानेवाली लघुनहर में 10 वर्षों से पानी मुहैया नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या यह सही है कि लघु नहर के चालू न होने से तीन पंचायतों भटसीमर पश्चिमी, मैलाम तथा गंगद्वार की 5 हजार एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित है ;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त लघु नहर में 30-40 स्लूइस गेट भी बना हुआ है जो निरर्थक क्षतिग्रस्त हो रहा है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त लघु नहर को चालू कराकर सिंचाई उपलब्ध कराना चाहती है ?

-----

### बसों का सत्यापन

\*131 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):

परिवहन :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि विभाग के अनुसार राज्य के सभी स्कूल प्रबंधकों को स्कूली बस और गाड़ियों का सत्यापन कराना अनिवार्य है, जिसके तहत स्कूल बसों को 22 नियमों का पालन करना आवश्यक है ;

(ख) क्या यह सही है कि स्कूल प्रबंधकों पर परिवहन विभाग के आदेश का भी कोई असर नहीं दिख रहा है, बगैर मानकों के स्कूली बसें बेरोकटोक चल रही हैं, उनपर न तो फोन नंबर है और न ही नाम, कई तो ऐसी हैं जिनको देखने से पता ही नहीं चलता कि वह स्कूल बस है ;

(ग) क्या यह सही है कि पटना में अभी तक किसी स्कूल ने बसों से संबंधित कागज

वेरीफिकेशन के लिए डी.टी.ओ. को नहीं दिया है ;

(घ) क्या यह सही है कि स्कूल बसों के द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के कारण स्कूली बच्चों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है ;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में स्कूल बस गाड़ियों का सत्यापन नहीं कराने वाले स्कूल प्रबंधकों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

----

### शस्त्र की अनुज्ञप्ति

\*132 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आदेश भारत सरकार द्वारा दिया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि सुमन कुमार, ग्राम+पो०- बीथो शरीफ, जिला गया द्वारा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत करने का आवेदन समर्पित किया गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस उपाधीक्षक, गया सदर, गया के पत्रांक- 111, दिनांक-27.01.2015 द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा किये जाने के बावजूद आज तक श्री कुमार के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं किया गया है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री कुमार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करना चाहती है ?

----

### राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में

\*133 श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

लघु जल संसाधन :-

क. क्या यह सही है कि राज्य के सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रख-रखाव के लिए पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है?

ख. क्या यह सही है कि उपरोक्त के लिए पंचायतों को राशि भी निर्गत कर दिया गया है ?

ग. क्या यह सही है कि इसके लिए पूरी प्रक्रिया का मॉनिटरिंग करने के लिए जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति भी बनाया गया है?

घ. क्या यह सही है कि राशि निर्गत होने के बाद भी समन्वय समिति के द्वारा अनुश्रवण के अभाव में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू नहीं किया जा रहा है जिसके कारण किसानों के रबी के फसल की सिंचाई ठप है ?

ङ. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बंद पड़े राजकीय नलकूपों को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

----

### दोषियों पर कार्रवाई

\*134 श्री सतीश कुमार (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर थाना के वृन्दावन में पूनम देवी, पिता- स्व. विरेन्द्र साह की नाबालिग बेटी को गांव के दबंगों द्वारा गला दबाकर मारने तथा साक्ष्य को मिटाने हेतु जला दिया गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड में थाना प्रभारी, कल्याणपुर द्वारा कांड अंकित नहीं करने तथा वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर कल्याणपुर थाना कांड सं.-216, दिनांक- 14.8.2019 अंकित किया गया है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कांड के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### भूखंड की उपलब्धता कबतक

\*135 श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राजकीय रेल पुलिस, पटना का अपना मैगजीन (शस्त्रागार) रेल पुलिस केन्द्र, पटना में जगह नहीं रहने के कारण पटना जिला बल के पुलिस केन्द्र में अवस्थित है एवं जगह नहीं रहने के कारण रेल पुलिस केन्द्र, पटना में पुरुष बैरक का भी अभाव है ;

(ख) क्या यह सही है कि पटना जिला बल का पुलिस केन्द्र का नवनिर्माण बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रेल जिला पटना का शस्त्रागार निर्माण प्रावधानित नहीं है ;

(ग) क्या यह सही है कि रेल जिला पटना के पुलिस केन्द्र से सटे पी.डब्लू.डी. का लगभग 09 कट्टा जमीन है, उसमें से 04 कट्टा जमीन उक्त केन्द्र से सटे राजकीय रेल पुलिस, पटना को उपलब्ध कराने पर उसके केन्द्र में ही शस्त्रागार एवं पुरुष बैरक निर्माण की समस्या का समाधान हो जायेगा, जो सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रेल पुलिस केन्द्र, चीनाकोठी, पटना से सटे पी.डब्लू.डी. के उक्त जमीन से 04 कट्टा भूखंड उपलब्ध कराना चाहेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### साप्ताहिक अवकाश

\*136 श्री सी.पी; सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा (विधान सभा):

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश विभागों में साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान है ;

(ख) क्या यह सही है कि कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग के जवानों को साप्ताहिक अवकाश का अधिकार प्राप्त नहीं है ;

(ग) क्या यह सही है कि लगातार कार्य पर रहने की वजह से जवान अवसाद से ग्रस्त होते जा रहे हैं ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं विभाग के पुलिस के जवानों को सोमवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने का इरादा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### भुगतान कब तक

\*137 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि आंगनवाड़ी सेविका को वेतन नहीं मिलती है, मानदेय दिया जाता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, फिर भी पूरी निष्ठा के साथ केंद्र का संचालन करने के पश्चात मानदेय के लिए भटक रहे हैं, दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के आंगनवाड़ी सेविकाओं का विगत मई 2015 से दिसंबर 2015 तक के बीच लगभग 2 से 8 माह तक का मानदेय बकाया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आंगनवाड़ी सेविका के बकाया मानदेय की राशि का भुगतान करना चाहती है यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?

-----

**मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्य हेतु वार्षिक कोष के सम्बन्ध में।**

**\*138 श्री अशोक कुमार अग्रवाल ( कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

**योजना एवं विकास :-**

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क. क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधान परिषद् सदस्य/विधान सभा सदस्य के लिए अपने क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्य हेतु वार्षिक कोष निर्धारित है ?

ख. क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के जिला परिषद् सदस्य /पंचायत समिति सदस्य के लिए अपने क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्य के लिए वार्षिक कोष निर्धारित नहीं है?

ग. क्या सरकार जिला परिषद् सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वार्षिक कोष निर्धारित करने का विचार करना चाहती है?

घ. यही उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कब तक नहीं तो क्यों?

-----

**पेंशनकारी का भुगतान**

**\*139 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

**समाज कल्याण :-**

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी) का ज्ञापांक-07, दिनांक- 30.03.2017 के द्वारा एक विधवा महिला श्रीमती रीना देवी, पति स्व. देवनारायण दिवाकर, ग्राम- गोरगामा, पंचायत- रामनगर, पत्रालय+ प्रखंड- फुलपरास,

जिला- मधुबनी के नाम लेखा संख्या-15/2016-17 के आधार पर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक- 01.03.2017 के प्रभाव से 400 रुपया प्रतिमाह पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर लाभुक को भुगतान का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन आजतक नहीं किया जा सका है ;

(ख) क्या यह सही है कि पेंशनधारी उक्त विधवा महिला ने एस.बी.आई., फुलपरास में अपनी संधारित बचत खाता संख्या- 34779289016 तथा आधारकार्ड संख्या- 242635715950 ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास के कार्यालय में समर्पित कर दिया था ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत पेंशन का अबतक पेंशनधारी को भुगतान न करने का क्या औचित्य हो सकता है और अब भी पेंशन का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

----

### वेतन वृद्धि

**\*140 श्री राजेश राम (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

**अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-**

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य की सभी पंचायतों एवं नगर निकायों के सभी वार्डों में अनुसूचित जाति के विकास के लिए विकास मित्रों की नियुक्ति की गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि विकास मित्रों का वेतन बहुत ही कम है जिस वेतन से परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विकास मित्रों के वेतन में वृद्धि करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

----

### सिंचाई सृजन

**\*141 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

**लघु जल संसाधन :-**

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि द्वितीय कृषि रोड मैप (2012-17) के अन्तर्गत सतही योजना से 10.249 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य था, जिसके

विरुद्ध 2.00 लाख हेक्टेयर अब तक सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है तथा 8.249 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन शेष रह गया है ;

(ख) क्या यह सही है कि द्वितीय कृषि रोड मैप (2012-17) में भू-जल सिंचाई योजना से 13.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध अबतक 2.116 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, शेष 11.244 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सृजन नहीं हो सका है ;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2012-17 में भू-जल प्रबंधन के तहत पांच वर्षों में कुल 30.362 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना था, जिसके विरुद्ध 6.839 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि लक्ष्य के अनुरूप सिंचाई क्षमता सृजन नहीं होने का औचित्य क्या है ?

-----